12.56 hrs.

MATTERS UNDER RULE 377

(i) Retrenchment of Employees in Food Corporation of India

SHRI VAYALAR RAVI: (Chirayinkil): With your kind permission, may I draw the attention of the Government to the alarming situation which has arisen in the Food Corporation of India. Everyday the unrest among the employees is mounting, especially after the retrenchment of 8000 employees. Sir, I am only one of those who want the streamlining of the whole organizational set-up of the Food Corporation.

There are a few thousands of people who have been recruited on a regular basis and they have had no intimation that they will be retrenched etc. Even though there are 4,000 people like that, they are facing this situation and these people have been recruited by the FCI with the hope that they will continue in their present jobs. When they joined the FCI they left their earlier jobs. They have been deprived of their earlier jobs and now this present occupation under the FCI. They have not made any job evaluation or study of the job situation. About 167 seats in the godowns and technical cadres, in coverage space alone, are lying vacant and in open storage there are more vacancies which can be absorbed. The management is taking only arbitrary decision. Already there is much tension there. I hope that the Government will come out within statement to as to how far the tension can be reduced and the functioning of the FCI can be normalised.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): Calling Attention should be admitted on this.

श्री मधु लिमये (बांका) अध्यक्ष महोदय, इस पर तो बहस ही कराइये ।

श्री हुकम चन्द कछवाय : (मुरैना) आप ने नोटिस दी है लोगों को ।

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): The impression that 4,000 people are to be retrenched is not correct. In fact some of the persons were recruited during the time of wheat procurement with the specific understanding that their employment is temporary for specific period. That staff alone is being affected because there is no work for them. We are very much concerned over it. The expenditure of the FCI should not mount up and consumers should not be penalised. We are trying our level best in the matter. This is what I would like to mention in regard to this subject.

(ii) Cancellation of Flights due to acute shortage of Aviation Fuel

श्री मधु लिमये (बांका) : अध्यक्ष महोदय, मैं नागरिक उड्डयन मंत्री का ध्यान उन समाचारों की ओर दिलाना चाहता हूं जिन में कहा गया है कि ऐवियेशन फ्यूअल के अभाव में इंडियन एयर लाइन्स की अधिकतर उड़ाने बन्द होने वाली हैं और इतना कम इंधन, फ्युअल मिलने वाला है कि जो बड़ी और लम्बी लाइन्स हैं उन के अलावा और शाखाओं पर भी उड़ानों का चलाना मुश्किल हो जायगा ।

अध्यक्ष महोदय, यह जो एक पेट्रोलियम का संकट हमारे ऊपर आया है उसी का ही यह एक पहलू है । पेट्रोलियम मंत्री बैठे हुए हैं, मैं दो, तीन बातों की ओर उन का ध्यान दिलाना चाहता हूं । अभी तक इस सदन को विश्वास में ले कर यह नहीं बताया

[श्री मधु लिमये]

गया कि सऊदी अरेबिया और दूसरे अरब देशों ने, हम को जो क्रूड आयल मिलता था, उस में कितने प्रतिशत की कमी की है? सरदार स्वर्ण सिंह ने कहा कि हम लोगों ने बातें की हैं और सऊदी अरेबिया का कहना है कि चूंकि हिन्दुस्तान दोस्त राष्ट्र है इस लिये उन के लिये कटौती नहीं की जायगी। तो फिर क्या वजह है कि बम्बई में जो ऐसो की रिफाइनरी है उस ने अपने उत्पादन को 25 प्रतिशत घटाया है। और कालटेक्स और बर्माशैल के बारे में भी सुना है कि उन्हों ने भी उसी तरह अपने उत्पादन में कटौती करने का निर्णय किया है? तो मैं मंत्री महोदय से सफाई चाहता हूं कि क्रूड आयल सप्लाई के बारे में वास्तव में स्थिति क्या है? ऐसो, बर्माशेल और कालटैक्स ने इतने बड़े पैमाने पर कटौती क्यों की है? ये बड़ी कम्पनियां जो अमरीका और दूसरे देशों की हू उनके पैट्रौल में जो कमी है उस की पूर्ति करती हैं। क्योंकि एक दफा पैट्रोल टैंकर पर चढ़ जाने के बाद कम्पनियों का यह पैट्रोल हो जाता है तो सऊदी अरेबिया का या अरब देशों का उस पर कैसे नियंत्रण रहेगा? हिन्दुस्तान के हिस्से का पेट्रोल दूसरे देशों को दिया जा रहा है, उसका भी वह खुलासा करें।

13.00 hrs.

तकरीबन डेढ़ करोड़ मिलियन टन क्रूड हम लोग आयात करते हैं। मुश्किल से सात मिलियन टन असम और गुजरात में आप निकाल पाते हैं। डेढ़ करोड़ हम लोग 500 करोड़ रुपया खर्च करके इस वक्त मंगा रहे हैं। भारत की रिफाइनरीज में जितना क्रूड इस्तेमाल किया जाता है। उसका सात प्रतिशत गायब होता है, वे लासिस हैं। आयात किए पेट्रोल का यह दस प्रतिशत हो जाता है। पांच सौ करोड़ का आयात अगर होता है तो पचास करोड़ रुपया रिफाइनरी लासिस में जाता है। मंत्री महोदय खुलासा करें इसका भी।

पिछली बार मैंने मंत्री महोदय से पूछा था कि जो सागर सम्राट आपने मंगाया है भूगर्भ शास्त्र की दृष्टि से ज्यालोजिकली बाम्बे हाई के इलाके में तेल की खोज करने के लिए उससे असली बाम्बे हाई के इलाके में आप खोदने के बजाय दूसरे ऐसे इलाके में खोद रहे हैं कि जहां तेल मिलने की सम्भावना कम है। इन बातों का आप खुलासा करें। वर्तमान जो संकट है तेल का इन समस्याओं को पहले हल किए बिना उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा। साथ-साथ कोयले से तेल की भी कोई आपकी योजना है? कोयला भी आप कहां से निकालेंगे? शिन्दे साहब से भी मैंने यह पूछा था और आप से भी मैं यह पूछ रहा हूं।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur): On reading to-day's newspapers, I learn that the highest authority of the Indian Airlines had clearly stated that it was going to affect the flights very seriously. You are aware of the reason why the Burmah-Shell and ESSO were not getting the supplies adequately. That was as a result of the cut in the import of crude. This question was raised sometime back also. And we requested the Minister to tell us whether the Government had finally made up its mind to take over these foreign oil companies. That is the real problem. Unless that is done, they may bully us and they may even shoot us with a double-barrelled gun—one for their profits

second point that I want to ask is this. The trouble is already going on—the trouble is not with Shri Borooah but with Shri Raj Bahadur—with the employees. I can assure you here and now that the employees stand by the Government. After taking advantage of this difficult situation I want to know whether hon. Minister for Civil Aviation, Shri Raj Bahadur will start negotiations immediately with the employees or not. At the same time I request the employees also to realise the gravity of the situation. I want an answer to this from the hon. Minister.

THE MINISTER OF PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI D. K. BOROOAH): Sir, I had been asked by the hon. Members, Shri Madhu Limaye and Shri Banerjee, to make a statement under Rule 377 for the shortage of aviation fuel at Bombay resulting in the cancellation of flights. I got the information immediately, and I would like to make a statement on this.

The information in this regard has appeared in the press this morning. This information does not appear to be correct. Sufficient stocks are available even as of now at Santa Cruz airport as well as the storage points of Bombay, in the refineries and in the installations of the oil companies to meet the full requirements of aviation fuel for Indian as well as foreign airlines.

It is confirmed that not a single aircraft has so far been cancelled or given reduced supplies of ATF. There are adequate stocks to meet the normal available requirements. What has been done is that the Indian Airlines has been asked or requested to make a contingency plan which could be put into operation in case the crude supply situation deteriorates. The Indian Airlines has not been requested to cancel any flights, and I reiterate that all that has been done is to have a contingency plan prepared.

So far as the other questions raised by Shri Madhu Limaye are concerned, I would be very happy to provide the information. In fact, in the debate in this House and in the very long debate in the Rajya Sabha, this was very adequately thrashed out. If it is suggested that a discussion is needed....

श्री मधु लिमये : तमाम मुद्दों का खुलासा आप एक वाक्य में कर सकते हैं ।

SHRI D. K. BOROOAH: Not today. This was the information that I got at 11.30 a.m.

श्री मधु लिमये : दो बातों का खुलासा आपने नहीं किया है । पंद्रह लाख टन रिफाइनरी लासिस हैं जिस में पचास करोड का घाटा हो रहा है । सागर सम्राट के बारे में क्या हुआ है । उस समय आपने गलत जवाब दिया था मेरे प्रश्न का ।

श्री देवकान्त बरुआ : गलत सवाल किया होगा, इसलिए गलत जवाब दिया ।

अध्यक्ष महोदय : साढ़े दस बजे आप नोटिस देते हैं और मिनिस्टर जवाब देता है । वह कोई एंसाइक्लोपीडिया तो है नहीं ।

श्री मधु लिमये : पचास करोड बचाना चाहता हूं । आप आगे बढ़ रहे हैं । देश के पास पैसा नहीं है । सात प्रतिशत रिफाइनरी लासिस के संबंध में जो पूछा है उसका जवाब दें । न राज बहादुर जी हैं और न देवकान्त बरुआ जी ही जवाब दे रहे हैं । समझ में नहीं आता है क्या हो रहा है ।

श्री देवकान्त बरुआ : स्पीकर के हुकम से इस सदन की कार्रवाई चलती है आपके हुकम से नहीं ।

MR. SPEAKER: I am not going to allow it. Let him please sit down. This was only to be raised under Rule 377.